KKM COLLEGE, PAKUR

Department of Sociology

B.A.(Honors)-Sem.06-Core-13-HonS

Paper Name: Industrial Sociology

(औद्योगिक समाजशास्त्र)

Prof. AVINASH TIWARI
Assistant Professor,
Department of Sociology,
KKM College, Pakur

Email ID-avinashtiwari557@gmail.com

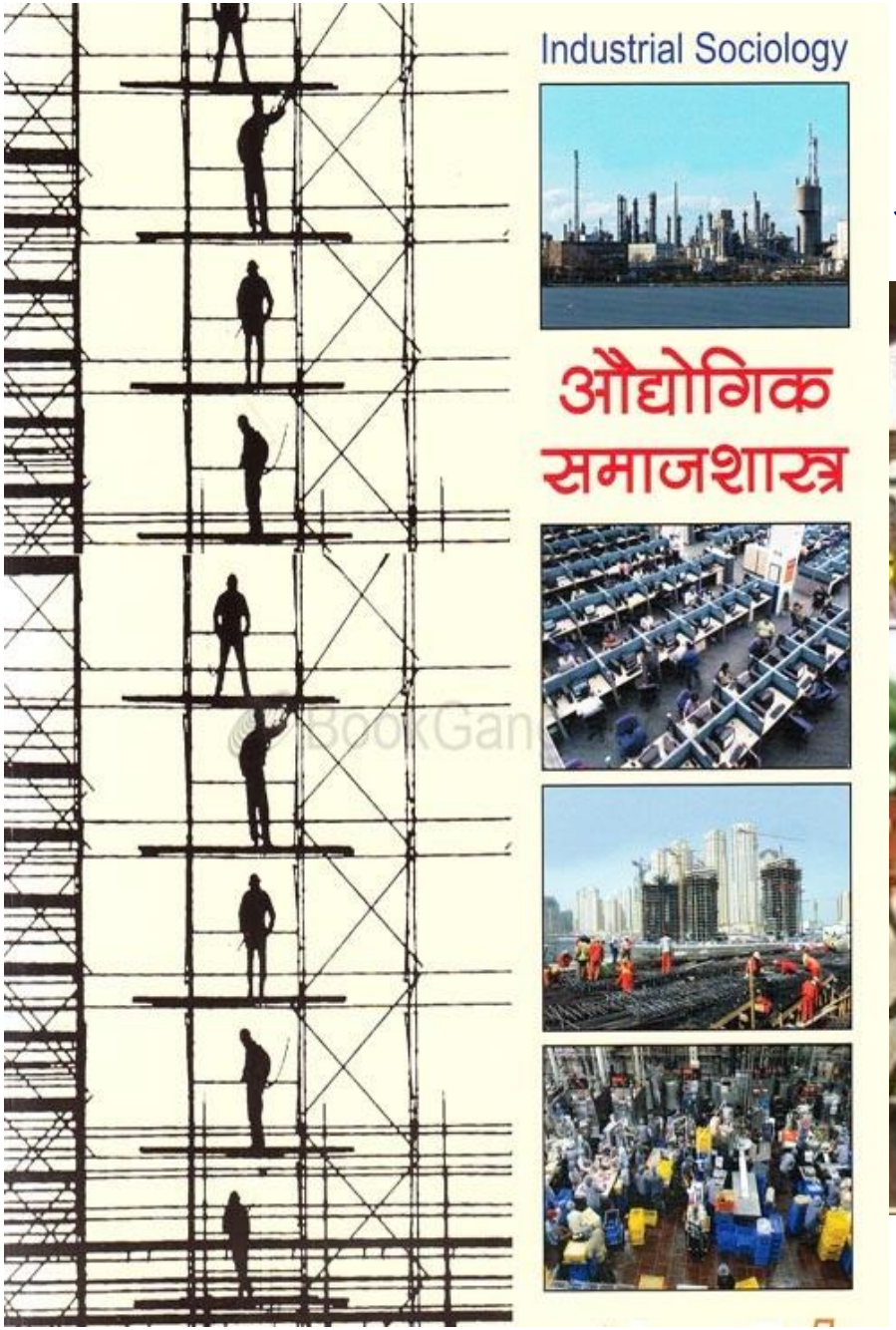

INDUSTRIAL SOCIOLOGY
औद्योगिक समाजशास्त्र)

औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा:--

- औद्योगिक समाजशास्त्र कार्यस्थल पर लोगों की प्रेरणा और व्यवहार का अध्ययन है।
- औद्योगिक समाजशास्त्र, काम के समाजशास्त्र के क्षेत्र के भीतर हाल ही में एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र की जांच करता है तकनीकी परिवर्तन, वैश्वीकरण, श्रम बाजार, कार्य संगठन, प्रबंधकीय प्रथाओं और रोजगार संबंधों में प्रवृत्तियों की दिशा और निहितार्थ, इन प्रवृत्तियों का आधुनिक समाजों में असमानता के बदलते पैटर्न और व्यक्तियों और परिवारों के बदलते अनुभवों से संबंधित है।

- **<u>परिभाषा</u>:--**
  - औद्योगिक समाजशास्त्र उन कारकों (तकनीकी, सहित) एक सामाजिक प्रणाली के रूप में उद्योग से संबंधित है आर्थिक, राजनीतिक) जो संरचना, कार्यों और उस प्रणाली में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।

  - औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे अधिक सटीक रूप से कहा जा सकता है कार्य संगठनों का समाजशास्त्र या अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्र।

  - विशेषण औद्योगिक का अर्थ है एक खंड में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और विधियों के अनुप्रयोग समाज, अर्थात्, जो सामान के उत्पादन और वितरण के आर्थिक कार्य से संबंधित है और समाज को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है।

- औद्योगिक समाजशास्त्र का विकास :--
  - जिन विषयों पर अंततः औद्योगिक समाजशास्त्र का लेबल लगाया जाता है, उनकी जांच आरंभिक भाग में शुरू हुई बीसवी सदी। शिक्षक, salespeople, चिकित्सकों जैसे व्यवसायों की गहराई से अध्ययन, शिकागो विश्वविद्यालय में 1920 में वेट्रेस, और मंत्री आयोजित किए गए थे। हालांकि, उप औद्योगिक समाजशास्त्र का अनुशासन आमतौर पर प्रसिद्ध पश्चिमी इलेक्ट्रिक के साथ शुरू हुआ माना जाता है शिकागो में नागफनी वर्क्स में आयोजित अनुसंधान कार्यक्रम। ये अध्ययन, ज़्यादा के दौरान आयोजित किए गए ग्रेट डिप्रेशन में, श्रमिक उत्पादकता में शामिल कारकों को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कब अध्ययन समाप्त हुआ, शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि सामाजिक वातावरण। काम श्रमिक के समूह और श्रमिकों दवारा प्रबंधन दवारा जिस तरह से व्यवहार किया गया था, उसका कार्यकर्ता पैर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा प्रदर्शन। हालांकि अब असहमति मौजूद है कि क्या उनके परिणाम वास्तव में उनका समर्थन करते हैं दावा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके निष्कर्षों ने रुचि रखने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों की कल्पना को पकड़ लिया श्रमिक उत्पादकता में और काम, श्रमिकों और काम से निपटने के लिए पर्याप्त अनुसंधान परियोजनाओं में संपन्न हुआ कार्यस्थल। उस अनुसंधान गतिविधि को अंततः औद्योगिक समाजशास्त्र के रूप में जाना गया और इसका प्रतिनिधित्व किया गया, एक समय के लिए, सबसे जीवंत समाजशास्त्र उप विषयों में से एक। अनुसंधान के उदाहरणों के लिए इस समय के दौरान आयोजित, अतिथि इस शोध के महत्व का एक उदाहरण प्रदान करता है जब वह उनकी एक परियोजना के परिणामों का वर्णन करता है। 1948 में, उन्होंने और उनकी टीम ने एक दो चरण की परियोजना शुरू की वह समुदाय जिसका यू.एस. स्टील प्लांट बंद होना था। पहले चरण में पौधे का अध्ययन होना था और शटडाउन से पहले समुदाय और दूसरे के बाद समुदाय का अध्ययन होना था बंद करना। पहला चरण पूरा होने के बाद, परिणाम स्टीलटाउन पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे। एक साल बाद, उन्होंने अमेरिकी स्टील के लिए जनसंपर्क प्रमुख से संपर्क किया और पूछा कि मिल अभी तक क्यों नहीं हुआ बन्द है। निर्देशक को आश्चर्य हुआ कि अतिथि ने सुना नहीं था कि क्या हुआ था। जाहिर है, सिर यू.एस. स्टील के लिए इंजीनियरिंग की रिपोर्ट पैढ़ी थी, मिल के कौशल के महत्व को महसूस किया कार्यबल, और ऑपरेशन में रखने के लिए मिल को अपग्रेड करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को आश्वस्त किया। निर्देशक यह कहकर निष्कर्ष निकाला गया, "आपके पास अध्ययन करने के लिए भूतों का शहर नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यदि आप एक यात्रा के लिए वापस चले गए चैंबर ऑफ कॉमर्स आपको मुख्य सड़क पर हीरो के रूप में परेड करेगा।

- **<u>औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति</u> :**
  - यह एक आर्थिक गतिविधि है जो कच्चे माल के प्रसंस्करण और वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है कारखाना। उद्योग का मतलब कड़ी मेहनत भी है। इसीलिए आमतौर पर कहा जाता है कि “अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए उद्योग में प्रवेश करें। "औद्योगिक समाजशास्त्र, इसके विकास और इसे ठोस आधार पर रखने की आवश्यकता है।" मानव जाति की प्रगति के पथ पर मनुष्य द्वारा महसूस किया गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद, जवाहरलाल नेहरू, पहले स्वतंत्र भारत के प्रधान मंत्री ने उद्योगों को नाम दिया।

  - औद्योगिक समाजशास्त्र मनुष्य के नरम कौशल के साथ अधिक व्यवहार करता है। यह राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह मदद करता है उत्पादन में वृद्धि और इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद (GOP) को बढ़ने में मदद मिलती है। गुणवत्ता के साथ और अधिक चूंकि प्रतियोगिता का सामना किया जा सकता है। आज, दोनों की ओर से, गुणवत्ता में रुचि की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है उद्योग और समाज। गुणवत्ता के लिए उच्चतर मांगों में अधिक रुचि के कई कारण हैं ग्राहकों से, अधिक प्रतिस्पर्धा, उत्पाद लाभप्रदता पर बेहतर लाभप्रदता और कानून की मांग। उद्यम में एकल विभाग पर काम के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है उन सभी कार्यों को जो इसके विकास, निर्माण और के दौरान उत्पाद के संपर्क में आते हैं उपयोग, इस काम में सहयोग करने के लिए। इसका मतलब है कि गुणवत्ता को इन सभी द्वारा माना और नियंत्रित किया जाना चाहिए कार्य: बाजार अनुसंधान, उत्पाद विकास, विनिर्माण इंजीनियरिंग, क्रय, उत्पादन, निरीक्षण, विपणन और बिक्री के बाद सेवा।

इन कार्यों के काम में समन्वय करना भी आवश्यक है गुणवत्ता पर कि उद्यम को गुणवत्ता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा जीवन बहुतों पर निर्भर है औद्योगिक उत्पादों पर तरीके; आश्रय, पोषण, संचार, स्वास्थ्य सेवा, काम, मनोरंजन और राष्ट्रीय सुरक्षा। इस प्रकार के उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं का एक बुनियादी पहलू यह है कि उनका उपयोग करने लायक होना चाहिए। असफलता उपयोग में चोट, असुविधा, मृत्यु या आर्थिक नुकसान हो सकता है। चूंकि ये सभी कार्य पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं किसी भी उत्पाद के मनु तथ्य में, शामिल लोग एक समूह बनाते हैं और इस प्रकार समाज का निर्माण होता है। की परिधि यह समाज भी प्रभावित होता है या इस मामले के लिए वे आम जनता से आते हैं और इस प्रकार कॉर्पोरेट की भूमिका निभा सकते हैं खेलने के लिए आता है। यह लोकप्रिय रूप से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के रूप में जाना जाता है।

- **<u>औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र</u>:--**

औद्योगिक समाजशास्त्र एक लागू अनुशासन है। इसका संबंध मानवीय संबंधों के अध्ययन से है उद्योगों के क्षेत्र में विकास और संचालन। यह उन सामाजिक अवधारणाओं से संबंधित है जिनकी प्रासंगिकता है उद्योग। यह कार्य स्थल या उद्योग के सामाजिक संगठनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पैटर्न का अध्ययन करता है औद्योगिक संगठनों में उनकी भूमिकाओं के संदर्भ में लोगों के बीच बातचीत। औद्योगिक संगठन अन्य विषयों जैसे- औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक द्वारा भी अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र। लेकिन वे विभिन्न तरीकों से उद्योग की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन कभी-कभी गोद में ले सकते हैं। औद्योगिक इंजीनियरिंग उत्पादों और उपकरणों के डिजाइन से संबंधित है। औद्योगिक प्रबंधन एक विज्ञान से अधिक एक कला है। औद्योगिक मनोविज्ञान का अध्ययन-का चयन कर्मियों, नौकरी से संतुष्टि, प्रेरणा और काम करने के लिए प्रोत्साहन, टीम भावना, दुर्घटना उच्चारण और इस तरह अन्य व्यक्तिगत मामले और व्यवहार संबंधी समस्याएं। अर्थशास्त्र ऐसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे कि कीमतें, मजदूरी, मुनाफा, पूर्ण रोजगार, वित्त, एकाधिकार, विपणन, कराधान, आदि लेकिन इनमें से कोई विज्ञान नहीं है इसका ध्यान औद्योगिक संगठनों के सामाजिक या मानवीय पहलुओं पर केंद्रित है। यह कार्य केवल द्वारा किया जाता है औद्योगिक समाजशास्त्र

औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक संगठन का अध्ययन तकनीकी या तकनीकी के रूप में नहीं करता है 5 आर्थिक संगठन, लेकिन उससे अधिक, एक सामाजिक या मानवीय संगठन के रूप में। यह सामाजिक पर बल देता है या औद्योगिक संबंधों में औपचारिक और अनौपचारिक कारक, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, टीम वर्क, संचार आदि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत इस तथ्य से प्रभावित होती है कि उनमें से एक है एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक प्लंबर, एक फैक्ट्री कर्मचारी, एक आशुलिपिक, एक बॉस, एक कर्मचारी, एक केंद्रीय नेता, या एक बेरोजगार व्यक्ति, हमारे सामने औद्योगिक समाजशास्त्र का कच्चा माल है। औद्योगिक समाजशास्त्र कार्यस्थल के कुल संगठन से संबंधित है। यह तीन अलग-अलग संगठनों के साथ भी काम करता है जिसे अलग पहचाना जा सकता है लेकिन परस्पर संबंधित: अर्थात, (ए) प्रबंधन संगठन, (बी) श्रमिकों के अनौपचारिक संगठन, और (सी) संघ संगठन (ए) 'प्रबंधन संगठन' को संदर्भित करता है प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संबंध। इसमें नीतियां, कार्यक्रम-संरचना और शामिल हैं प्रबंधन का कार्य। इसका मुख्य जोर श्रमिकों द्वारा विकसित औपचारिक संबंधों पर है प्रबंधन के साथ। (b) श्रमिकों के 'अनौपचारिक संगठन' में अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है कार्यकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से।

इस तरह के संबंध व्यक्तियों और छोटे समूहों द्वारा स्थापित किए जाते हैं कारखाने या उद्योग के भीतर। इस तरह के संगठन गुट, गिरोह, मैत्री समूहों के रूपों को मानते हैं। बैंड आदि ये संगठन अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के अनौपचारिक मानदंडों को विकसित करते हैं अंगार। (ग) संघ संगठन से तात्पर्य ट्रेड यूनियनों की भूमिका और भागीदारी या भागीदारी से है संघ की गतिविधियों में कार्यकर्ता। ट्रेड यूनियन औद्योगिक अशांति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं औद्योगिक शांति बनाए रखना। वे श्रमिकों के औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों को भी नियंत्रित करते हैं। इन उद्योग के तीन संगठन कार्य स्थल की भौतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं प्रबंधन की सोच, सरकारी और अन्य सामाजिक नियंत्रण, कर्मचारियों के व्यक्तित्व और उनके अन्य संगठनों में भूमिका निभाने का अनुभव।

- **<u>औद्योगिक संबंध की अवधारणा, प्रकृति व अर्थ</u>:--**
- औद्योगिक श्रम, वास्तव में, वृहत् समाज का ही एक अंग है। श्रमिक के रूप में वह उत्पादन का सक्रिय साधन है, किन्तु साथ ही, वह उपभोक्ता भी है। समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा व भूमिका है। अस्तु, उसे उद्योग, परिवार व बृहत् समाज के अंग के रूप में एक ही साथ भूमिका का निर्वाह करना होता है। तीनों ही स्तरों पर मानवीय सम्बन्धों का समुचित स्तर बना रहना व इन भूमिकाओं में एक प्रकार का सामंजस्य भी बना रहना अनिवार्य है। कार्य स्थल श्रमिकों के लिए मानसिक तनाव व मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण न बनें, तभी यह 'भूमिकाओं का सामंजस्य' श्रमिक प्राप्त कर सकेगा।

- **औद्योगिक सम्बन्ध की परिभाषा**:--

  - **अग्निहोत्री (1970:1)** के विचार से, "औद्योगिक सम्बन्ध शब्द श्रमिकों/ कर्मचारियों व प्रबन्धकों के मध्य उन सम्बन्धों को व्यक्त करता है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से श्रम संघ तथा नियोक्ता के बीच सम्बन्धों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।"

  - **वी. बी. सिंह (1971 : 9)** के अनुसार, "औद्योगिक सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आधुनिक उद्योग में नियोक्ता व श्रमिकों में पाया जाता है, जिनकी नियमन राज्य द्वारा विभिन्न अंशों में किया जाता है तथा जो सामाजिक तत्वों व अन्य संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। इसमें राज्य के कार्यकलापों का अध्ययन, वैधानिक प्रणाली, श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के संगठन (संख्यात्मक स्तर पर) तथा आर्थिक स्तर पर पूँजीवादी व्यवस्था, औद्योगिक संगठन, श्रम शक्ति नियोजन तथा बाजार सम्बन्धी घटक सम्मिलित होते हैं।"

  - **इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (1961 : 297)** में औद्योगिक सम्बन्ध की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि "औद्योगिक सम्बन्ध का विचार राज्य तथा नियोक्ताओं के सम्बन्धों और श्रमिक एवं उनके संगठनों तक विस्तृत है। इस प्रकार, इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्बन्ध, सामूहिक सुझाव प्रणाली (श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच), सामूहिक सम्बन्ध (नियोक्ताओं एवं श्रम संघों के बीच), तथा राज्य द्वारा की गयी अविश्यक व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया
    जाता है।"

इस प्रकार, औद्योगिक सम्बन्ध की अवधाराणा के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत श्रम शक्ति एवं नियोक्ता तथा उसके प्रबन्ध तंत्र के मध्य स्थापित गुणात्मक सम्बन्धों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका सीधा असर श्रमिकों की
उत्पादकता व उनके कार्य संतोष पर पड़ता है। भारत के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (यथा संशोधित 1984) के अन्तर्गत परिवाद निवारण प्रक्रिया की सम्पूर्ण वैधानिक
विधि तथा सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया एवं मशीनरी को औद्योगिक सम्बन्ध के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

- **औद्योगिक संबंध के भागीदार**
  - जॉन डनलप (1951) के विचार से, "औद्योगिक समाज निश्चित रूप से औद्योगिक सम्बन्धों को जन्म देता है, जिन्हें श्रमिकों, प्रबन्धकों तथा सरकार के अन्तसंबंध कहा जाता है।" ये तीनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा औद्योगिक सम्बन्धों को ढ़ाचा निर्मित करते हैं। तीनों भागीदारों का विवरण निम्न प्रकार है :

- **श्रमिक एवं उनके संगठन –**
  - इसके अन्तर्गत श्रमिकों के वैयक्तिक गुण, सामाजिक-सास्कृतिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर, योग्यता, कुशलता, कार्य के प्रति
    रूचि, एवं उनके नैतिक चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है। श्रमिक संगठन यदि सही नेतृत्व वाला हो तो औद्योगिक इकाई में असहयोगात्मक वातावरण का सृजन हो सकता है, जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित कर उत्पादकता में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

- **<u>प्रबन्धक एवं उनके संगठन</u>:–**
  - प्रबन्धकों के संगठन एवं कार्य समूह औद्योगिक सम्बन्धों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसमें संगठनों की प्रकृति, विशिष्टता, उनके उद्देश्य, आंतरिक संप्रेषण, प्रस्थिति एवं अधिकार प्रणाली, इन संगठनों समूहों के अन्य संगठनों एवं समूह के साथ सम्बन्ध आदि पर जोर दिया जाता है। प्रबंधकों के संगठन एवं समूहों के साथ नियोक्ता के किस प्रकार के सम्बन्ध है तथा नियोक्ता एवं प्रबन्धकों के संगठन मिलकर राज्य (यानी सरकार) से किस प्रकार के सम्बन्ध रख पाते हैं, इसका प्रभाव भी औद्योगिक सम्बन्धों की संरचना पर पड़ता है। अच्छे नियोक्ता व प्रबन्ध संगठन सामाजिक दायित्वों का समुचित अनुपालन करके तथा वैधानिक नियमों का सम्यक् निर्वहन करके सरकार से अच्छे सम्बन्ध बना सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता है।
- **<u>राज्य अथवा सरकार की भूमिका</u>:–**
  - राज्य के कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के औद्योगिक सम्बन्ध के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित प्रस्तावों व निर्देशों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय संधियों के अनुरूप नीति निर्धारण करके बेहतर औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना समाहित है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा ही विभिन्न कानून बनाए जाते है, इनमें संशोधन व सुधार किया जाता है तथा बेहतर औद्योगिक महौल बनाने के लिए उपयुक्त मशीनरी, प्रक्रियाओं व न्यायिक ढांचे का निर्माण भी किया जाता है।

- **औद्योगिक सम्बन्ध के उद्देश्य:--**

कुछ अमेरिकी विद्वानों का मत है कि औद्योगिक सम्बन्धों का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम विकास करना, श्रमिकों व नियोक्ताओं के मध्य वांछित कार्यकारी संबंध स्थापित करना तथा भौतिक संसाधनों की अपेक्षा मानव संसाधनों को इच्छित गति प्रदान करना है। वैसे, औद्योगिक सम्बन्धों का मूल उद्देश्य दो पक्षों, अर्थात् श्रमिकों एवं प्रबन्धकों, के मध्य अच्छे तथा स्वस्थ सम्बन्धों का विकास करना है ताकि औद्योगिक शांति एवं उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। औद्योगिक सम्बन्धों के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार है :

- श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना; इसके लिए दोनों पक्षों में एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति समझ व आदर भाव उत्पन्न करना।
- औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना ताकि अधिक उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।
- पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अधिकतम रोजगार एवं अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना।
- श्रम बदली व अनुपस्थिति की दर में कमी करना।
- औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना; इसके लिए नीति निर्धारण व प्रबन्धन में श्रमिक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों को सिविल सोसायटी का अंग बनाना, ताकि उनका व्यवहार तर्क आधारित तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हो सके।

- हड़ताल, तालाबन्दी, घेराव आदि में कमी लाने का प्रयास करना; इसके लिए श्रमिकों को उपयुक्त मजदूरी, अच्छी कार्य दशाएँ, अच्छी रहन सहन की दशाएँ तथा अन्य अनुषंगी लाभ सुनिश्चित कराना। साथ ही, श्रमिकों को कार्य के प्रतिअधिक समर्पित बनाना।

- औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक असन्तुलन को दूर करना तथा आस-पास के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाना। इसमें औद्योगिक सम्बन्धों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है; इसके लिए राज्य को भी आवश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए।

- कुल सामाजिक लाभ में बढ़ोत्तरी करना।

- श्रमिकों व प्रबन्धकों के बीच अविश्वास की खाइंर् पाटकर उनमें सम्पकर् सेतु कायमकरना।

- औद्योगिक विवादों को यथासम्भव टालना व मधुर सम्बन्ध बनाना।

- उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर देश के विकास को बढ़ावा देना।

- **<u>औद्योगिक संबंधों के निर्धारक कारक</u>:-**
  - औद्योगिक सम्बन्ध शून्य में विकसित नहीं होते। ये उस वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं, जिसमें श्रमिक रहते व कार्य करते हैं। इन कारकों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं :–

    (अ) संस्थागत कारक (ब) आर्थिक कारक
- **<u>संस्थागत कारकों के अन्तर्गत</u>**

  राजकीय नीति, श्रम कानून व विनियम, श्रमिक संघ, नियोक्ता संघ तथा सामाजिक संस्थाएँ (जैसे कि समुदाय, जाति, संयुक्त परिवार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक मूल्य, परंपरायें, आदि) सम्मिलित हैं। इसमें कार्य के प्रति अभिरूचि व रूचि, शक्ति के आधार, स्तर व अनपु ेर् ण, आद्यै ोगिक प्रणाली आदि भी सम्मिलित है।
- **<u>आर्थिक कारकों के अन्तर्गत</u>**

  आर्थिक विचारधारा (जैसे कि पूँजीवादी या साम्यवादी), औद्योगिक ढाँचा (जैसे कि पूँजीवादी ढाँचा), आर्थिक संस्थान, व्यक्तिगत, कम्पनी तथा सरकारी स्वामित्व, पूँजीगत ढ़ाँचा (तकनीकी सहित), श्रम शक्ति की प्रकृति और उसका गठन, बाजार की शक्तियों का स्वरूप, बाजार में श्रम की माँग एवं आपूर्ति की स्थिति आदि सम्मिलित है।

आर0 ए0 लेस्टर ने श्रम व प्रबन्धन के मध्य सम्बन्धों को प्रदर्शित करने के लिए तीन घटक बताए हैं :

1. आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक शक्तियाँ, जो एक ओर नीति निर्धारण तथा प्रबन्ध की कार्यवाही की तथा दूसरी ओर श्रम संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों की कार्यवाही को प्रभावित करती है ;
2. प्रबन्धकों व श्रमिकों के बीच शक्ति सम्बन्धों का ढाँचा, तथा
3. श्रम एवं प्रबन्धन के बीच शक्ति का संतुलन।
लेस्टर प्रथम प्रकार के कारकों को मूल कार्य घटक तथा शेष दो प्रकार के कारकों को शकित ढाँचा घटक कहते हैं।

– इन सभी घटकों में समन्वय इस प्रकार स्थापित किए जाने की आवश्यकता है कि औद्योगिक शांति को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि उद्योगों में मानवीय सम्बन्धों में सुधार के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति, औद्योगिक प्रजातंत्र का विकास तथा लाभ एवं निर्णय में श्रम एवं प्रबन्धन की सहभागिता के बृहत्तर लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

- **<u>औद्योगिक सम्बन्धों का विषय क्षेत्र:</u>--**

औद्योगिक सम्बन्ध कोई असाधारण सम्बन्ध नहीं हैं, बल्कि यह एक क्रियात्मक अंतर्निर्भरता है, जिसमें ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक, तकनीकी, व्यावसायिक, राजनैतिक, वैधानिक तथा अन्य चरणों का अध्ययन किया जाता है।

<u>वी0 पी0 माइकल (1984)</u> के शब्दों में, "यदि हम औद्योगिक विवादों (अर्थात अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव) को किसी वृत्त का केन्द्र बिन्दु मानें तो वह वृत्त विभिन्न भागों में बँट जाएगा। उदाहरणार्थ, कार्य की दशाओं का अध्ययन मुख्यत: मजदूरी के स्तर तथा रोजगार की सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में किया जाता है, जोकि आर्थिक क्षेत्र में आती हैं। विवादों का उद्‌ग म तथा विकास इतिहास के क्षेत्र में आता है; उससे होने वाला सामाजिक विघटन समाजशास्त्र के क्षेत्र में ; श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं सरकार तथा समाचार पत्रों आदि के विचार समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में ; उनकी सांस्कृतिक अंतक्रियाएँ सांस्कृतिक नृगत्व शास्त्र के क्षेत्र में ; सरकार की नीति जो विवादों के मामलों में अपनाई जाती है, राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में ; विवाद के वैधानिक तत्व विधि के क्षेत्र में ; श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के मध्य सम्बन्ध के बारे में अंतराष्ट्रीय सहयोग एवं संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में ; विवादों के प्रभाव (जिनमें श्रम नीति पर प्रशासन शामिल हो) लोक प्रशासन के क्षेत्र में ; और तकनीकी विषय (जैसे ताप नियंत्रण तथा विवेकीकरण की विधियों का उपयोग) तकनीकी क्षेत्र में;तथा लाभ अथवा
हानि का आँकलन गणित के क्षेत्र में आता है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक सम्बन्धों का विषय क्षेत्र विभिन्न विज्ञानों एवं ज्ञान क्षेत्रों की अंतर्निभरता का प्रमाण है। ये सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यवसायिक तकनीकी आदि कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होते हैं।

- औद्योगिक सम्बन्ध मानवीय धारणाओं और कार्य प्रक्रियाओं का मिश्रण होते हैं। सम्बन्ध अच्छे होंगे या बुरे, यह व्यक्तिगत भावनाओं और कार्य प्रक्रियाओं पर निर्भर
  करता है।
- धारणाओं के अन्तर्गत विश्वास एवं पहचान, भावकता, एवं कार्यपरिणति के लिए संकल्प भावना सम्मिलित होती है। इन्हें समझना मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय है।
- कार्य प्रक्रियाओं में, प्राथमिकता निर्धारण, चयन प्रक्रिया, निर्णय, आदेश पालन, सुझाव एवं सुधार प्रक्रिया, कार्य गहनता, अनुसंधान प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं। इनमें
  सुधार से संगठन एवं उसके सामाजिक दायित्व की पूर्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'सहयोग की स्वतंत्रता तथा सहयोग के अधिकार की रक्षा, संगठित होने के
  सिद्धान्त की क्रियान्विति, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, सामूहिक समझौता, मध्यस्थता, पंचनिर्णय, तथा अधिकारियों एवं व्यापारियों के संगठनों के बीच सहयोग को
  श्रम सम्बन्धों के अन्तर्गत सम्मिलित किया है।'

- **<u>डेल योडर के विचार से</u>**,
  - "औद्योगिक सम्बन्धों के अन्तर्गत भर्ती, चयन, श्रमिकों का शक्षण सेविवर्गीय प्रबन्ध, सामूहिक सौदेबाजी सम्बन्धी नीतियाँ सम्मिलित की जाती।"

    इसप्रकार, औद्योगिक सम्बन्धों का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसके विषय क्षेत्र के अन्तर्गतउपरोक्त के साथ ही, निम्न बातों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

  - औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्तियों के बीच अच्छे सम्बन्धों का निर्माण एवं उनका संधारण।
  - मानवीय विकास को प्रोत्साहन
  - कर्मचारियों में टीम भावना का निर्माण एवं उनमें संगठन के प्रतिनिष्ठा उत्पन्न करना।
  - आपसी सम्मान, भाईचारा एवं औद्योगिक संस्थान में कौटुम्बिक सम्बन्धों का विकास।
  - औद्योगिक संस्थान में शांति का वातावरण निर्मित करना।
  - औद्योगिक उत्पादन एवं राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन।
  - समाज कल्याण को बढ़ावा।
  - परिष्कृत नियमावली एवं कार्य प्रणाली का निर्धारण।
  - उत्पादक – उपभोक्ता – सरकार के मध्य विश्वास व सद्भाव का वातावरण निर्मित करना।

- **औद्योगीकरण नगरीकरण संबंध:-**

औद्योगीकरण' एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव-समूह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग-धन्धों का बोलबाला होता है। वस्तुत: यह आधुनीकीकरण का एक अंग है। बड़े-पैमाने की ऊर्जा-खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातुकर्म की अधिकता आदि औद्योगीकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली का बड़े पैमाने पर संगठन है।

नगरीय जनसंख्या वृद्धि का कारक:-

यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। मशीनों के अविष्कार के परिणामस्वरूप श्रमिक, शिल्पी और कारीगर बेकार हो गए। इन बेरोज़गार श्रमिकों को नगर क्षेत्रों में रख लिया गया। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों के प्रयोग और औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणामस्वरूप नगरीकरण का सूत्रपात हुआ। भारत में यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका की तरह नगरीकरण की क्रिया नहीं हुई। भारत में नगरीकरण के निम्नलिखित कारण रहे-

- **रेलों का विकास**:-
  - रेलों के विकास ने भारत के व्यापार क्षेत्र में क्रान्ति ला दी। भारत में रेलों का विकास दो आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया गया था |
  - पहला प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
  - दूसरा व्यापारिक केन्द्रों पर वस्तुऐं और कच्चा माल एकत्रित करने के लिए
- **अकाल**:-
  - 19वीं शताब्दी में भारत में पड़ने वाले अकाल भी नगरीय जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार न मिल सकने के कारण ग्रामीण जनसंख्या रोज़गार की तालाश में नगरों की ओर चल पड़ी। इस प्रकार 1872-1881 और 1891-1991 की अवधि में भीषण अकाल पड़ने के कारण नगरों की तरफ जनसंख्या का पलायन हो गया।
  - नगरीय जीवन का आकर्षण
  - नगर जीवन में कुछ ऐसे आकर्षण हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं पड़ते। अतः धनी ज़मींदारों ने भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नगरों में बसने की प्रवृत्ति उभरी।
  - उद्योगों का विस्तार
  - नये उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विस्तार होने के कारण श्रमशक्ति नगरों में खपने लगी।

- **नगरों में स्थायी रोज़गार:-**
  - » भूमिहीन श्रमिक वर्ग जिनका मूल संबंध कृषि से था, ग्राम तथा नगरों के बीच आने-जाने वाली श्रम शक्ति का ही एक अंग था। इस वर्ग के जिन लोगों को नगर क्षेत्रों में स्थाई रोज़गार अथवा अपेक्षाकृत ऊंची मज़दूरी मिल गई, वे वहीं बस गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण के विकास में उद्योगों का विकास अन्य सभी देशों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा किन्तु भारत में इसका प्रभाव इतना सशक्त नहीं था। भारत में ऐसे नगरों की संख्या बहुत कम है जिनका विकास नये उद्योगों के कारण हुआ हो।

- **नगरीकरण और आर्थिक विकास में संबंध:-**

किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के निम्नलिखित तीन लक्षण मुख्य होते हैं-

- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ताकि लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके।
- निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में कमी।
- बेरोज़गार की दर एवं आकार में कमी।

आंकड़ों के आधार पर जब कुल जनसंख्या में नगर जनसंख्या के अनुपात और प्रति व्यक्ति आय में यह संबंध गुणांक निकाला जाता है तो वह 0.5 आता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नगरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में सकरात्मक संबंध है। किंतु यही सह सहसंबंध गुणांक जब जनसंख्या और दैनिक स्थिति बेरोज़गारी के बीच निकाला जाता है तो वह 0.18 आता है जो यह संकेत करता है कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई।

- **पर्यावरण पर प्रभाव:-**

पर्यावरण की दृष्टि से भारत की भयावह तस्वीर का खुलासा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में किया गया है। उसके अनुसार 2020 तक भारत विश्व में ऐसा देश होगा, जिसके हवा, पानी, जमीन और वनों पर औद्योगीकरण का सबसे ज्यादा दबाव होगा, वहां पर्यावरण बुरी तरह बिगड़ जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की सांसें टूटने लगेंगी और उसके लिए इस विकास की कीमत चुकाना टेढ़ी खीर होगी। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की मानें तो जलवायु में भीषण परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जानी-मानी शोध पत्रिका 'प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसायटी' में ब्रिटिश व स्विस वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि बिजलीघरों, फैक्ट्रियों और वाहनों में जीवाष्म ईंधनों के जलने से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार जलवायु परिवर्तन का न केवल स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बल्कि प्रमुख खाद्यों के उत्पादन में भी कमी आएगी। अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कंसलटेटिव ग्रुप के अनुसार 2050 तक भारत में सूखे के कारण गेहूँ के उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की कमी आएगी। गेहूँ की इस कमी से भारत के 20 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर होंगे। दिनों-दिन बढ़ती आबादी और औद्योगीकरण के कारण आने वाले सालों में भारत में खाद्य संकट का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल, वातावरण में औद्योगिक काल में पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेद्रण 30 प्रतिशत ज्यादा हुआ है। इससे असहय गर्मी व लू बढ़ेगी और खड़ी चट्टानों के गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी। बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण तनाव या हाईपोथर्मिया जैसी बीमारियां होंगी और दिल तथा श्वास संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा होगा।

- **जीवों के लिए संकटकारक:--**

दुनिया भर में औद्योगीकरण से पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में 30 प्रतिशत उभयचर प्राणियों, 23 प्रतिशत स्तनपायी और 12 प्रतिशत चिड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। यह अंधाधुंध बढ़ते औद्योगीकरण का ही नतीजा है कि हर साल 45 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो रहे हैं। दुनिया की 60 प्रतिशत प्रमुख नदियों पर बांध बना दिए गए हैं, जिससे मछलियां 50 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से दुनियाभर में पक्षियों की 122 प्रजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जिसमें से 28 भारत में हैं।

- **कार्बन गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि:-**

औद्योगीकरण का एक अन्य नुकसान कार्बन गैसों के उत्सर्जन के रूप में सामने आया। विकास की दौड़ में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों, गाड़ियों, एसी जैसी चीजों को तो हमने खूब प्राथमिकता दी, लेकिन इनसे निकलने वाले कार्बन गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। आज चीन दुनिया में सबसे अधिक कार्बन गैसों का उत्सर्जन करता है। वहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर 21 टन है, जो दुनिया भर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का दस प्रतिशत है। उसके बाद अमरीका, यूरोपियन यूनियन के देशों और रूस का स्थान आता है। भारत का स्थान इस मामले में पांचवां है और यहां प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर 1.2 टन है, जो दुनिया भर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का केवल तीन प्रतिशत है। यही वजह है कि भारत अपने विकास कार्यक्रमों पर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं चाहता।

- **स्वचालन:-**

स्वयंचालित मशीनें (Automatic Machines) ऐसी मशीनें हैं जो मानव प्रयास के बिना भी किसी प्रचालन चक्र को पूर्णत: या अंशत: संचालित करती हैं। ऐसी मशीनें केवल पेशियों का ही कार्य नहीं करतीं वरन् मस्तिष्क का कार्य भी करती हैं। स्वयंचालित मशीनें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वयंचालित हो सकती हैं।[1] ये निम्नलिखित प्रकार का कार्य कर सकती हैं:

1. माल तैयार करना
2. माल को सँभालना
3. माल का निरीक्षण करना
4. माल का संग्रह करना
5. माल को पैक करना

- **लाभ:-** स्वयंचालित मशीनों के लाभ ये हैं :

- 1. श्रम की लागत की कमी,
- 2. उत्पादन समय में कमी अर्थात् नियमित समय में अधिक उत्पादन करना,
- 3. प्रचालक की आवश्यक कुशलता में कमी का होना,
- 4. तैयार माल के गुणों में सुधार,
- 5. अदल बदल में उत्कृष्टता,
- 6. प्रचालन श्रांति में कमी का होना, तथा
- 7. औजारों और उनकी व्यवस्था में कमी का होना।

इन लाभों के कारण जहाँ पहले केवल मनुष्यों से काम लिया जाता था, जैसे कार्यालयों, गृह और सड़क के निर्माणों, खनन, कृषि और कृषि के अन्य कामकाजों तथा अनेक उद्योग धंधों में वहाँ अब स्वयंचालित मशीनें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्य कर रही हैं।

- **स्वचालन का प्रभाव**

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार भारत में औपचारिक काम-धंधों से जुड़े 60 प्रतिशत काम-धंधे “मध्यम-कौशल” से जुड़े हैं. ये काम हैं, लिपिकीय कार्य, बिक्री, सेवा, कुशल कृषि और कारोबार से जुड़े काम. ये सभी काम स्वचालित हो सकते हैं. इस प्रकार, स्थूल स्तर पर स्वचालन के अर्थ व्यवस्था से जुड़े अनेक निहितार्थ हैं और कामगारों के लिए सूक्ष्म-स्तर पर कार्यस्थल के स्तर पर अनेक निहितार्थ हैं. स्थूल स्तर पर स्वचालन से होने वाले परिवर्तन के तीन आयाम हैं: कुशल कारीगरों की माँग में परिवर्तन, कामगारों की पुनः तैनाती में लैंगिक असमानता और कारखानों को पुनः संगठित करना. सबसे पहले तो “कुशलता” की परिभाषा से ही यह अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा कि कामगारों की स्वचालन के साथ किस हद तक अनुकूलता है. उदाहरण के लिए, शारीरिक या विषय-वस्तु की कुशलता के बजाय “सिस्टम की कुशलता” की माँग के अंतर्गत जटिल समस्याओं के समाधान की क्षमता और मानवीय धारणाओं से जुड़ी सामाजिक कुशलता की कहीं अधिक माँग होगी.

सके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के काम-धंधों पर लगने वाले समय और प्रयासों से होने वाले सापेक्ष लाभ में बहुत अंतर होता है. इसका अर्थ यह है कि कामकाजी जीवन के संतुलन से कुछ तरह के काम-धंधों में सुधार होगा और शेष काम-धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाएँगे. उदाहरण के लिए, महिलाओं के वर्चस्व वाले कॉल सैंटर के काम, फुटकर काम और प्रशासनिक कार्य खत्म हो जाएँगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों के वर्चस्व वाले डेटा क्लीन अप और डिजिटल अवसंरचना वाले कामों की माँग बढ़ जाएगी. इसके कारण इस बदलाव में लैंगिक पक्ष महत्वपूर्ण हो जाएगा. अंततः स्वचालन और कामगारों की पुनः तैनाती के कारण “मानवीय क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म” पर फ़र्मों को फिर से व्यवस्थित करना होगा, जिनमें किसी भी स्थान पर बसे कामगारों को काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा. इसके कारण फ़र्म और कामगारों की रणनीतियों के बीच अल्पकालीन स्तर पर विचलन हो जाएगा.

सूक्ष्म स्तर पर, स्वचालन के कारण काम का अर्थ ही बदल जाएगा. काम-धंधों का अधिकाधिक वर्णन विशिष्ट “कार्यों” के रूप में किया जाएगा. स्वतंत्र कामगार विशिष्ट दर पर खास तरह के काम ही करेंगे. कार्यस्थल पर पर्यवेक्षण के पदक्रम के स्थान पर वितरित और सुदूर टीमों के साथ सहयोग करने वाले नैटवर्क होंगे. इसके कारण कामगारों की प्रेरणा और संवाद में भारी परिवर्तन होगा. इन परिवर्तनों के कारण नये काम-धंधों के अनुबंध का असर न्यूनतम वेतन संबंधी आकस्मिक नियोक्ता के दायित्व, सामाजिक लाभ और सामूहिक सौदेबाजी के कारण आई कमी पर भी पड़ेगा.

- **औद्योगिक क्रांति:-**

अट्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही **औदयोगिक क्रान्ति** (Industrial Revolution) के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारम्भ होकर पूरे विश्व में फैल गया। "औदयोगिक क्रांति" शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आरनोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक "लेक्चर्स ऑन दि इंड्स्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड" में सन् 1844 में किया।

औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरम्भ हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीकें आयीं और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। कोयले को जलाकर बने वाष्प की शक्ति का उपयोग होने लगा। शक्ति-चालित मशीनों (विशेषकर वस्त्र उद्योग में) के आने से उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। उन्नीसवी सदी के प्रथम दो दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। इसके परिणामस्वरूप दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण को गति मिली। उन्नीसवी शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैल गयी।

अलग-अलग इतिहासकार औद्योगिक क्रान्ति की समयावधि अलग-अलग मानते नजर आते हैं जबकि कुछ इतिहासकार इसे क्रान्ति मानने को ही तैयार नहीं हैं।

अनेक विचारकों का मत है कि गुलाम देशों के स्रोतों के शोषण और लूट के बिना औद्योगिक क्रान्ति सम्भव नही हुई होती, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिये पूंजी अति आवश्यक चीज है और वह उस समय भारत आदि गुलाम देशों के संसाधनों के शोषण से प्राप्त की

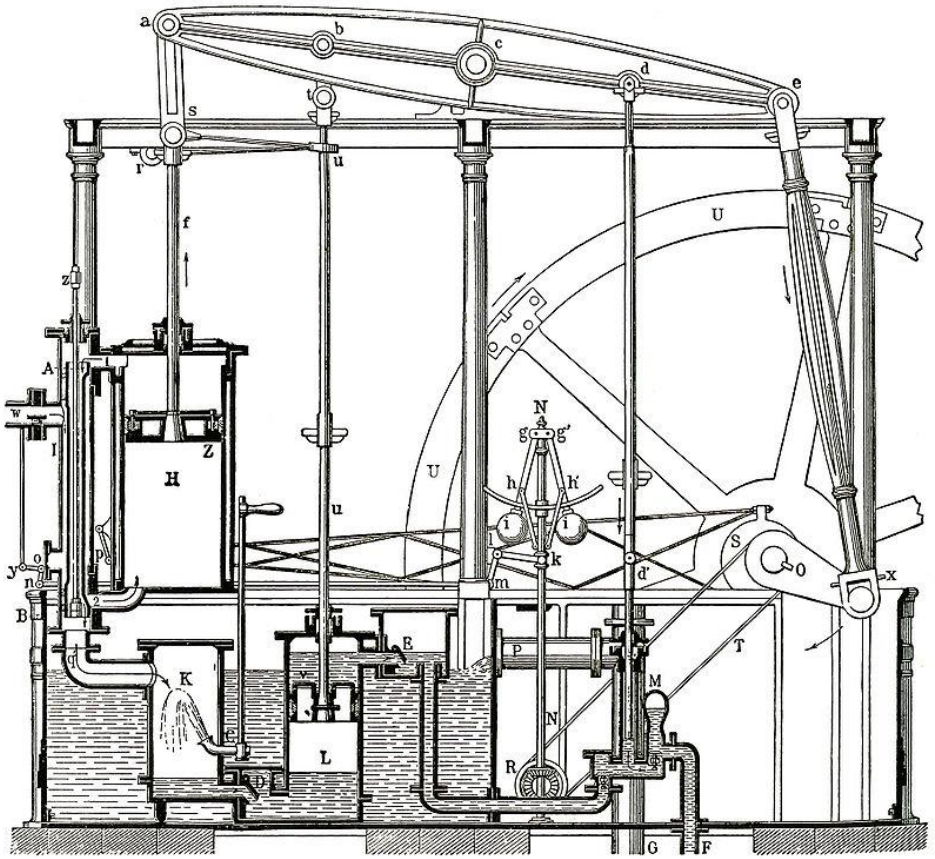

- **वाष्प इजन** आद्यौगिक क्रांति का प्रतीक था।

- **औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण:**

कृषि क्रांति

- जनसंख्या विस्फोट
- व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति
- उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार
- पूंजी तथा नयी प्रौद्योगिकी
- पुनर्जागरण काल और प्रबोधन
- राष्ट्रवाद
- कारखाना प्रणाली

- **औद्योगिक क्रांति के परिणाम**

आर्थिक परिणाम:

उत्पादन में असाधारण वृद्धि: कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र एवं अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई जिससे औद्योगिक देश धनी बनने लगे। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान हो गई। वहां औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक एवं व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए अपनी पूंजी की प्रतिभूतियां (Securities) बेचना आरंभ किया। इस तरह उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया।

- **<u>सामाजिक परिणाम</u>:**

जनसंख्या में वृद्धि: औद्योगिक क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। वस्तुतः कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भोजन आवश्यकता की पूर्ति की। दूसरी तरफ यातायात के उन्नत साधनों के माध्यम से मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कार भोजन आवश्यकता की पूर्ति की। दूसरी तरफ यातायात के उन्नत साधनों के माध्यम से मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न की पूर्ति करना संभव हुआ। बेहतर पोषण एवं विकसित स्वास्थ्य एवं औषधि विज्ञान के कारण नवजात शिशु एवं जीवन की औसत आयु में वृद्धि हुई। फलतः मृत्यु दर में कमी आई।

नए सामाजिक वर्गों का उदय: औद्योकिग क्रांति ने मुख्य रूप से तीन नए वर्गों का जन्म दिया। प्रथम पूंजीवादी वर्ग, जिसमें व्यापारी और पूंजीपति सम्मिलित थे। द्वितीय मध्यम वर्ग, कारखानों के निरीक्षक, दलाल, ठेकेदार, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि शामिल थे। तीसरा श्रमिक वर्ग जो अपने श्रम और कौशल से उत्पादन करते थे।

मानवीय संबंधों में गिरावट: परम्परागत, भावानात्मक मानवीय संबंधों का स्थान आर्थिक संबंधों ने ले लिया। जिन श्रमिकों के बल पर उद्योगपति समृद्ध हो रहे थे उनसे मालिन न तो परिचित था और न ही परिचित होना चाहता था। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीन और तकनीकी ने मानव को भी मशीन का एक हिस्सा बना दिया।

नैतिक मूल्यों में गिरावट: नए औद्योगिक समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। भौतिक प्रेगति से शराब और जुए का प्रचार बढ़ा। अधिक समये तक काम करने के बाद थकावट मिटाने के लिए श्रमिकों में नशे का चलन बढ़ा। इतना ही नहीं औद्योगिक केन्द्रों पर वेश्यावृति फैलने लगी। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ने से भ्रष्टाचार एवं अपराधों को बढ़ावा मिला।

- **भारतीय मजदूर संघ:-**

भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना भोपाल में महान विचारक स्व. दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिवस २३ जुलाई १९५५ को हुई। भारत के अन्य श्रम संगठनों की तरह यह किसी संगठन के विभाजन के कारण नहीं बना वरन एक विचारधारा के लोगों का सम्मिलित प्रयास का परिणाम था।

यह देश का पहला मजदूर संगठन है, जो किसी राजनैतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं, बल्कि मजदूरों का, मजदूरों के लिए, मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतंत्र मजदूर सगठन है। स्थापना के पश्चात द्रुत गति से उन्नति करते हुए आज यह देश में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ तथा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ संबंधित, एक इकाई भारतीय संरक्षण कामगार संघ आयुध निर्माणी देहूरोड पुना महाराष्ट्र में है

श्रमिक संघ:-

'श्रमिकों के सभी प्रकार के समान हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया, श्रमिकों का संगठन **श्रमिक संघ** कहलाता है। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 1850 ई. से 1870 ई. के बीच हुई थी। आद्योगिकीकरण के साथ-साथ इस क्षेत्र में अनेक बुराइयाँ, जैसे- अधिक समय तक श्रमिकों से काम लेना, कठोर श्रम, आवास की असुविधा, कम पैरिश्रमिक, मृत्यु दर में अधिकता आदि व्याप्त थीं। इन बुराईयों को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने कई कारख़ाना अधिनियम बनाये, पर इन अधिनियमों द्वारा इन क्षेत्रों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। श्रमिकों ने औपनिवेशिक राज्य से लड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके परिणामस्वरूप 1884 ई. में भारत के पहले **श्रमिक संघ**, 'बम्बई मिल हैण्ड ऐसोसिएशन' की स्थापना एन.एम.लोखण्डे के नेतृत्व में की गई।

- **संगठन का उद्देश्य:-**

श्रमिकों के इस संगठन ने मराठी भाषा में 'दीनबन्धु' नामक अख़बार भी प्रकाशित किया। 1897 ई. में 'अमलगमेटिड सोसाइटी ऑफ़ रेलवे सर्वेन्टस ऑफ़ इण्डिया एण्ड बर्मा' की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त 1905 ई. में 'कलकत्ता प्रिन्टर्स यूनियन', 1907 ई. में 'बम्बई पोस्टल यूनियन' और और 1910 ई. में 'कामगार हितवर्धक सभा' की स्थापना हुई। इन संगठनों का एकमात्र उद्देश्य था- फैक्ट्री प्रणाली में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। मज़दूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलवे, जिसका नाम 'ग्रेट इण्डियन पेनन्सुलर रेलवे' था, 1899 ई. में मज़दूरी, काम के घण्टों तथा अन्य सेवा शर्तों में सुधार को लेकर हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनीतिक आन्दोलनों के फलस्वरूप 'श्रमिक आन्दोलन' को भी बल प्राप्त हो गया था।